



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2011/चैत्र 29, 1933

No. 651]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2011/CHAITRA 29, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2011

का.आ. 766(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 20 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति श्री विद्या भूषण गुप्ता को 1 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 70 वर्ष की आयु को प्राप्त हो जाने तक, जो भी पहले हो, समय-समय पर यथासंशोधित उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1(3)/2010-सीपीयू]

जी. एन. श्रीकुमारन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2011

S.O. 766(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (3) of Section 20 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government, on the recommendation of the Selection Committee, hereby appoints Mr. Justice Vidya Bhushan Gupta (Retd.), Delhi High Court, as whole-time

Member of the National Consumer Disputes Redressal Commission with effect from the forenoon of the 1st day of April, 2011, for a period of five years, or until he attains the age of 70 years, whichever is earlier, on the terms and conditions prescribed in the Consumer Protection Act, 1986 read with the Consumer Protection Rules, 1987 as amended from time to time.

[F.No. 1(3)/2010-CPU]

GN. SREEKUMARAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2011

का.आ. 767(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 20 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति श्री विकास रामचन्द्र किंगावकर को 1 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 70 वर्ष की आयु को प्राप्त हो जाने तक, जो भी पहले हो, समय-समय पर यथासंशोधित उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1(3)/2010-सीपीयू]

जी. एन. श्रीकुमारन, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2011

**S.O. 767(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (3) of Section 20 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government, on the recommendation of the Selection Committee, hereby appoints Mr. Justice Vikas Ramachandra Kingaonkar (Retd.), Bombay High Court, as whole-time Member of the National Consumer Disputes

Redressal Commission with effect from the forenoon of the 1st day of April, 2011, for a period of five years, or until he attains the age of 70 years, whichever is earlier, on the terms and conditions prescribed in the Consumer Protection Act, 1986 read with the Consumer Protection Rules, 1987 as amended from time to time.

[F. No. 1(3)/2010-CPU]

G. N. SREEKUMARAN, Jt. Secy.